Drishti IAS

करेंट अफेयर्स हरियाणा

दिसंबर 2022

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

हरियाणा **3**

- हरियाणा ने MBBS बांड नीति में किये कई अहम बदलाव 3
- हरियाणा के पाँच खिलाड़ियों को मिला अर्जुन अवॉर्ड 3
- मनु भाकर ने राष्ट्रीय शूटिंग में जीते चार स्वर्ण 4
- मेघना चौटाला बनीं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष 4
- हरियाणा में परियोजनाओं के लिये कॉन्ट्रैक्ट समझौतों में एन्हांसमेंट के लिये दिशा-निर्देश जारी 5
- प्रदेश में स्थापित होगा जीएसटी ट्रिब्यूनल 5
- गुरुग्राम में 500 एकड़ में बनेगा जैव विविधता पार्क व झील 6
- राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में लागू होगा कामन कैडर 7
- हरियाणा ने जलवायु परिवर्तन पर संशोधित राज्य कार्ययोजना (एसएपीसीसी-2) को दी मंज़ूरी 7
- हरियाणा का वाटर एटलस तैयार 8
- हरियाणा के गाँवों में अब शहरों की तर्ज पर उठेगा कूड़ा 8
- एक अप्रैल से हरियाणा में हिन्दी में भी मिलेंगे अदालतों के आदेश 9
- हिसार का एयरपोर्ट अभी अंतर्राष्ट्रीय नहीं 10
- हरियाणा के सभी गाँवों की फिरनी पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे व लाइटें 10
- हरियाणा ने जीता स्कॉच गोल्ड अवार्ड 11
- सॉफ्टवेयर से तैयार होगी प्रदेश में ज़मीन की फर्द 12
- हैफेड रेवाड़ी में स्थापित करेगा ऑयल-मिल 12
- महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर हरियाणा व केंद्र सरकार में समझौता 13
- हरियाणा में रेल अवसंरचना परियोजनाओं के लिये 128 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण स्वीकृत 13
- 'मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना' का विस्तार 14
- राज्य में अब स्टेज- 3 व 4 के कैंसर पीड़ितों को मिलेगी 2500 रुपए मासिक पेंशन 14
- हरियाणा अनुसूचित जाति (एससी) आयोग का गठन 15
- सूर्य नमस्कार अभियान 15
- ड्यूकेन मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी के मरीज़ों को मिलेगी 2500 रुपए पेंशन 16
- सोनीपत में बनेगा प्रदेश का पहला खेलकूद विश्वविद्यालय 16
- पंचायतों और नगर पालिकाओं को और अधिक स्वायत्तता देगी हरियाणा सरकार 17
- डिजिटल मीडिया सेक्शन को मिला राज्य स्तरीय पुरस्कार 17

नोट :

हरियाणा

हरियाणा ने MBBS बांड नीति में किये कई अहम बदलाव

चर्चा में क्यों?

30 नवंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक के बाद बताया कि राज्य ने MBBS छात्रों की मांगों को ध्यान में रखते हुए MBBS बांड मामले में कई अहम बदलाव किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- MBBS बांड नीति में नए बदलावों के बाद जहाँ एक ओर राज्य ने सात साल के बांड एग्रीमेंट की समय सीमा घटाकर 5 वर्ष कर दी है, वहीं इस पाँच वर्ष में PG की पढ़ाई को भी शामिल किया है यानी एक तरह से अब बांड की समय सीमा दो साल होगी।
- इसके अलावा बांड राशि को जो पहले 40 लाख थी उसे घटाकर 30 लाख कर दिया है। इसमें से यदि फीस घटा दी जाए तो यह राशि करीब 25 लाख होगी और लड़कियों के लिये इसमें दस फीसदी की छूट का निर्णय भी लिया गया है। इस राशि में संस्थान की फीस शामिल नहीं है।
- इस नीति में यह भी फैसला लिया गया है कि यदि MBBS की पढ़ाई कर रहे किसी छात्र के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका परिवार बांड राशि भरने के लिये बाध्य नहीं होगा।
- इस नीति में बताया गया है कि पढ़ाई के बाद एक साल के भीतर MBBS छात्र को सरकारी नौकरी (अनुबंधित) दी जाएगी। इसके अलावा यदि कोई छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद प्राइवेट नौकरी करता है और उसका वेतन सरकार द्वारा मेडिकल ऑफिसर को दिये जा रहे वेतन से कम है तो उसे तब तक बांड की राशि नहीं देनी होगी जब तक उसका वेतन मेडिकल ऑफिसर के वेतन के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं होता। ऐसी स्थिति में सरकार उसे अनुबंधित नौकरी ऑफर करेगी।
- गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने चिरायु, आयुष्मान भारत और निरोगी हरियाणा जैसी अनेक योजनाएँ चलाई हैं जो प्रदेश के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिये शुरू की गई हैं। इसके अलावा राज्य में सभी ज़िलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और सरकारी अस्पताल खोले जा रहे हैं जिसकी वजह से सरकार को आने वाले समय में काफी संख्या में डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ेगी।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज व नर्सिंग कॉलेज इत्यादि की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 में प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज थे और एमबीबीएस सीटें केवल 700 थी। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 6 कॉलेज खोले गए और अब एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर 1735 हो गई है।
- उन्होंने बताया कि राज्य की हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है। कई ज़िलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं तथा इन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य पूरा होते ही एमबीबीएस के लिये 3000 छात्रों के दाखिले किये जाएंगे।
- राज्य में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई गई हैं और भविष्य में भी इन सीटों को बढ़ाया जाएगा ताकि डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके।
- प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 1000 की जनसंख्या के ऊपर एक डॉक्टर की तैनाती के लक्ष्य को पूरा किया जाए। यह मापदंड विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित किया गया है।

हरियाणा के पाँच खिलाड़ियों को मिला अर्जुन अवॉर्ड

चर्चा में क्यों?

30 नवंबर, 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार-2022 समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा देश के 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इनमें हरियाणा के पाँच खिलाड़ी भी शामिल हैं।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा के जिन पाँच खिलाड़ियों को अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है, उनमें शामिल हैं- मुक्केबाज अमित पंघाल, एथलीट सीमा पूनिया, कुश्ती खिलाड़ी अंशु मलिक व सरिता मोर और बैडमिंटन के पैरा खिलाड़ी तरुण ढिल्लों।
- अमित पंघाल की जगह उनकी माँ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से यह पुरस्कार ग्रहण किया।
- उल्लेखनीय है कि भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार है। वर्ष 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। खेल में अपनी उत्कृष्टता के लिये खेल हस्तियों को समर्पित यह पुरस्कार खेल रत्न के बाद दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार बेहतरीन प्रदर्शन, लीडरशिप क्वालिटी, खेल भावना और अनुशासन के लिये दिया जाता है।
- अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, एक काँस्य प्रतिमा और सम्मान पत्र दिया जाता है।

मनु भाकर ने राष्ट्रीय शूटिंग में जीते चार स्वर्ण

चर्चा में क्यों?

1 दिसंबर, 2022 को हरियाणा की मनु भाकर ने भोपाल में खेली जा रही 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 मीटर पिस्टल में दाँव पर लगे सभी तीन स्वर्ण पदक जीत लिये। मनु ने 25 मीटर पिस्टल के सीनियर और जूनियर वर्ग का स्वर्ण जीता। इससे पहले उन्होंने सीनियर और जूनियर प्रतिस्पर्धा के टीम इवेंट में भी स्वर्ण जीते थे।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा की 20 साल की निशानेबाज मनु भाकर ने महिला वर्ग के फाइनल में सीआरपीएफ की पुष्पांजलि राणा को 33-27 से पराजित किया, जबकि जूनियर वर्ग के फाइनल में उन्होंने अपने ही राज्य की विभूति भाटिया को 32-24 से हराया। विभूति ने महिला वर्ग में और तेलंगाना की मेघना सादूला ने जूनियर वर्ग में काँस्य जीता।
- उल्लेखनीय है कि 65वीं राष्ट्रीय पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन 20 नवंबर से 10 दिसंबर, 2022 तक भोपाल के बिशनखेड़ी स्थित मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में किया जा रहा है।
- इस राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में लगभग 5 हज़ार से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।

मेघना चौटाला बनीं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष

चर्चा में क्यों?

5 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी मेघना चौटाला को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया (TTFI) का अध्यक्ष चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

- मेघना चौटाला टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। टीटीएफआई की ओर से इस आशय के आदेश जारी कर दिये गए हैं। इनसे पहले उनके पति और उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी टीटीएफआई के अध्यक्ष रह चुके हैं।
- मेघना चौटाला ने बताया कि वह इस नई ज़िम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगी और विशेषरूप से युवाओं एवं महिला खिलाड़ियों के लिये फेडरेशन में स्वस्थ तथा बेहतर माहौल देने का प्रयास करेंगी।
- गौरतलब है कि राष्ट्रीय चैंपियन कमलेश मेहता को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए महासचिव के रूप में कार्यभार दिया गया है और पटेल नागेंद्र रेड्डी को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है।

हरियाणा में परियोजनाओं के लिये कॉन्ट्रैक्ट समझौतों में एन्हांसमेंट के लिये दिशा-निर्देश जारी

चर्चा में क्यों ?

7 दिसंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि राज्य सरकार ने परियोजनाओं के लिये कॉन्ट्रेक्ट समझौतों में पारदर्शी और एक समान तरीके से एन्हांसमेंट के लिये नये सिरे से दिशा-निर्देश जारी किये हैं। यह निर्णय हाल ही में सरकार के ध्यान में एन्हांसमेंट वृद्धि में अनियमितता के कई मामले सामने आने के बाद लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव ने बताया कि निर्णय के अनुसार संरचनात्मक डिजाइन और कार्य के दायरे में संशोधन के मामले में सक्षम प्राधिकारी निर्णय लेंगे। यदि आवंटित कार्य की लागत 1 करोड़ रुपए से कम है, तो मौजूदा व्यवस्था जारी रह सकती है।
- यदि आवंटित कार्य की लागत 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो, इस स्थिति में 10 प्रतिशत तक विभाग के प्रशासनिक सचिव, 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें विभाग के प्रशासनिक सचिव बतौर सदस्य शामिल हैं, निर्णय लेगी।
- इसके अलावा, 20 प्रतिशत से अधिक के मामले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी, जिसमें विभाग के प्रभारी मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे, निर्णय लेगी।
- उन्होंने बताया कि निविदा दरों, अनुबंध समझौते में दिये गए मूल्य समायोजन तथा विभागीय आपूर्तियों के लिये आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय के आपूर्ति दरों में परिवर्तन के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि के संबंध में वर्तमान प्रणाली जारी रहेगी।
- उन्होंने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, अंबाला, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और फरीदाबाद मंडलों के आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, संगठनों के मुख्य प्रशासकों, प्रबंध निदेशकों, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और जिला उपायुक्तों को पत्र जारी कर निर्देश जारी किये गए हैं। इस निर्देश का जारी होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से सख्त अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रदेश में स्थापित होगा जीएसटी ट्रिब्यूनल

चर्चा में क्यों ?

7 दिसंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशनों के सहयोग से प्रदेश में पहली बार आयोजित एक-दिवसीय कर संवाद कार्यक्रम में बताया कि प्रदेश में टैक्स करदाताओं व अधिवक्ताओं की सुविधा के लिये जीएसटी ट्रिब्यूनल बनेगा, जिसके आगामी मार्च तक शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिये जीएसटी काउंसिल को सिफारिश की जा चुकी है।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जीएसटी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिये हिसार व गुरुग्राम में 2 जॉइंट ईटीसी रेंज अपील कार्यालय खोले जाने की घोषणा भी की।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में जीएसटी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिये करदाताओं, अधिवक्ताओं व आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को साझा मंच प्रदान करते हुए मंडल स्तर पर जीएसटी आमने-सामने शुरू किया जाएगा।
- शुरुआती स्तर पर इसे प्रदेश के सभी 6 मंडलों - अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम तथा फरीदाबाद में शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक माह में एक बार करदाता, टैक्स अधिवक्ता व अधिकारी मिलकर टैक्स संबंधी समस्याओं का निवारण करेंगे।
- इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने जीएसटी के लिये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने का आह्वान किया और बताया कि एक साल में सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन करवाने वाले तीन अधिवक्ताओं को सम्मानित किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने टैक्स अधिवक्ताओं द्वारा रखी गई मांग को ध्यान के रखते हुए प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में टैक्स संबंधी विषयों से जुड़ी पुस्तकों की लाइब्रेरी खोलने की भी घोषणा की।

नोट :

- उन्होंने कहा कि ये लाइब्रेरी डीआईटीसी कार्यालय परिसर में खोली जाएगी। इसके साथ ही टैक्स बार एसोसिएशन के बैठने के लिये कैंटीन की सुविधा वाले प्रतीक्षा हॉल भी बनाया जाएगा, जहाँ टैक्स संबंधी सुनवाई के लिये कार्यालय में आने वाले टैक्स अधिवक्ता अपने करदाताओं के साथ बैठकर विचार-विमर्श करने के साथ-साथ अपनी बारी का इंतजार भी कर सकेंगे।
- मुख्यमंत्री ने कर संग्रहण में हरियाणा प्रदेश की अन्य राज्यों के साथ तुलना करते हुए बताया कि हरियाणा की आबादी देश की आबादी का केवल 2 प्रतिशत है वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में हरियाणा का क्षेत्रफल 1.6 प्रतिशत है, लेकिन देश के कर संग्रहण में हरियाणा का हिस्सा 6 प्रतिशत है।

गुरुग्राम में 500 एकड़ में बनेगा जैव विविधता पार्क व झील

चर्चा में क्यों ?

8 दिसंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने राज्य के गुरुग्राम ज़िले के सोहना के दमदमा गाँव में आयोजित कार्यक्रम में गुरुग्राम ज़िले के 3 गाँवों दमदमा, खेड़ला और अभयपुर में लगभग 420 एकड़ में जैव विविधता पार्क का निर्माण और लगभग 80 एकड़ में दमदमा झील का पुन:निर्माण वाली वृहद परियोजना की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- यह परियोजना गुरूजल, हरियाणा सीएसआर ट्रस्ट तथा ई वाई फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जाएगी।
- इस परियोजना के लिये मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय राज्य मंत्री की उपस्थिति में उपायुक्त निशांत कुमार यादव, जो गुरूजल के चेयरमैन हैं और हरियाणा राज्य सीएसआर ट्रस्ट के संयुक्त सचिव भी हैं, ने ई वाई फाउंडेशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये। ई वाई फाउंडेशन की तरफ से संस्था के अध्यक्ष बाला चंद्र राजा रमन ने समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- इस अवसर पर गाँव दमदमा में आयोजित कार्यक्रम में जैव विविधता पार्क व दमदमा झील के पुर्ननिर्माण की परियोजना के अलावा गुरूजल की पानी संरक्षण के लिये चलाई जा रही गतिविधियों पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि यह कंपनी इस प्रोजेक्ट पर स्वेच्छा से 70 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कंपनियों को अपना सीएसआर फंड सही ढंग से सामाजिक कार्यों में खर्च करने को प्रेरित करने के लिये हरियाणा सीएसआर ट्रस्ट बनाया गया है। पिछले एक वर्ष में कंपनियों ने इस ट्रस्ट के माध्यम से प्रदेश में 542 करोड़ रुपए सीएसआर के खर्च किये हैं।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में कम से कम एक हजार करोड़ रुपए सीएसआर के माध्यम से सामाजिक कार्यों में लगें। इस पैसे को पर्यावरण, जल संरक्षण, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि जैव विविधता पार्क और झील के विकास के अलावा, गुरुग्राम तथा नूंह ज़िलों में अरावली की पहाड़ियों में लगभग 10 हज़ार एकड़ में जंगल सफारी बनाने का कार्य भी प्रस्तावित है। इससे भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे।
- ई वाई फाउंडेशन के अध्यक्ष बाला चंद्र राजा रमन ने बताया कि उनकी कंपनी सीएसआर के दायरें में नहीं आती फिर भी स्वेच्छा से इस प्रोजेक्ट पर खर्च कर रही है। इस प्रोजेक्ट को विकसित करने में टैरी, सिडार, आईआईटी, कोलंबिया युनिवर्सिटी आदि संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा।
- यह परियोजना चार चरणों में विकसित होगी। पहले चरण में क्षेत्र के पेड़-पौधों व मिट्टी आदि का अध्ययन करने के साथ नर्सरी का निर्माण व झील की सफाई की जाएगी। दूसरे चरण में वॉटर शैड मैनेजमेंट व पौधारोपण की शुरूआत होगी, तीसरे चरण में झील का विकास और चौथे चरण में पौधारोपण किया जाएगा।
- दमदमा झील का जीर्णोद्धार चार साल में और जैव विविधिता पार्क विकसित करने का कार्य 10 साल में पूरा होगा।

नोट :

राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में लागू होगा कामन कैडर

चर्चा में क्यों ?

11 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार ने एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी के बाद अब राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में कामन कैडर लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिये पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य में मेडिकल कॉलेजों में कामन कैडर का प्रस्ताव विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पास होने के बाद इसे नए शिक्षा सत्र से सभी मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल यूनिवर्सिटी में लागू किया जा सकेगा। कामन कैडर लागू होने के बाद किसी भी मेडिकल कॉलेज के नियमित कर्मचारी को दूसरे मेडिकल कॉलेजों में भेजा जा सकेगा।
- जानकारी के अनुसार राज्य सरकार का प्रयास है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में भी एक समान सेवा नियम हों।
- वर्तमान में राज्य के स्वास्थ्य विश्वविद्यालय रोहतक और अन्य मेडिकल कॉलेजों के अलग-अलग नियम हैं। यहाँ पर कॉलेज ही अपने स्तर पर भर्तियाँ करते रहे हैं। करीब छह माह पहले सरकार ने भर्तियों को अपने हाथ में लिया है और मुख्यालय ही सभी मेडिकल कॉलेजों के लिये भर्तियाँ निकाल रहा है।
- वर्तमान में राज्य में दिक्कत ये है कि एक मेडिकल कॉलेज में तैनात टीचर्स, डॉक्टर और अन्य स्टाफ को दूसरे में तबादला नहीं किया जा सकता। इससे सरकार को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये सरकार सभी मेडिकल कॉलेजों के लिये एक जैसे नियम और सेवा शर्तें बनाने जा रही है। पूरा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और सभी मेडिकल कॉलेजों के निदेशक भी इस पर सहमति जता चुके हैं।
- उल्लेखनीय है कि एक साल पहले भी राज्य सरकार ने कामन कैडर को लागू करने की कोशिश की थी। लेकिन पीजीआई की टीचर्स एसोसिएशन और अन्य कर्मचारियों के विरोध के चलते इसे लंबित छोड़ दिया गया था।
- दरअसल, नियमित डॉक्टर और कर्मचारी इस पॉलिसी का विरोध इसलिये कर रहे हैं, क्योंकि उनका तर्क है कि जब उनकी नियुक्ति हुई थी तो उन्हें संबंधित मेडिकल कॉलेज ही स्टेशन बताया गया था। अब कई कई साल से सेवा देने के चलते उन्हीं शहरों में कर्मचारियों और डॉक्टरों ने अपने मकान आदि बना लिये हैं। दूसरा तर्क ये है कि अगर सभी का एक समान कैडर बना तो इससे काफी संख्या में कर्मचारियों की सीनियरिटी प्रभावित होगी।
- हरियाणा सरकार की मंशा है कि राज्य के हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाए। नौ ज़िलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। अगले सत्र से जींद, भिवानी और नारनौल में मेडिकल कॉलेज शुरू करना है। यहाँ पर नए स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया लंबी है। इसलिये राज्य सरकार चाहती है कि पहले से ही मेडिकल कॉलेज और पीजीआई में तैनात स्टाफ डॉक्टरों व कर्मचारियों को इन कॉलेजों में तबादला करके भेजा जाए।

हरियाणा ने जलवायु परिवर्तन पर संशोधित राज्य कार्ययोजना (एसएपीसीसी-2) को दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में संपन्न हुई जलवायु परिवर्तन पर हरियाणा राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में जलवायु परिवर्तन पर संशोधित राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी- 2) को मंज़ूरी प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव ने बताया कि जलवायु परिवर्तन पर संशोधित राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी चरण-2) 2021-30 स्वीकृत संशोधित योजना के अनुसार, 73 कार्य प्रस्तावित किये गए हैं, जिनमें से 37 अनुकूलन से जुड़े हैं। 28 मिटिगेशन से और 8 रणनीतियाँ अनुकूलन और मिटिगेशन दोनों से संबंधित हैं।
- 10 वर्षों (2021-30) में इन गतिविधियों के लिये कुल प्रस्तावित बजट 39,371.80 करोड़ रुपए है। अंतिम अनुमोदन के लिये इस कार्य योजना को राष्ट्रीय स्तर की स्टीयरिंग कमेटी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) को प्रस्तुत किया जाएगा।

नोट :

- उन्होंने बताया कि संशोधित योजना का उद्देश्य 8 राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों पर विचार करते हुए लक्ष्यों को संरेखित और पुन:परिभाषित करना है।
- इन 8 एनडीसी में सतत् जीवन शैली, स्वच्छ आर्थिक विकास, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता को कम करना, गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की हिस्सेदारी बढ़ाना, कार्बन सिंक (वन) अनुकूलन को बढ़ाना, वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व क्षमता निर्माण करना शामिल हैं।
- बैठक में मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को 2030 तक वर्केबल मिटिगेशन और अनुकूलन एक्शन एवं रणनीति के लिये योजनाओं, रणनीतियों और कार्यों को अपडेट करने के निर्देश दिये इसके अलावा, एसएपीसीसी की निगरानी और मूल्यांकन के लिये राज्य सलाहकार समूह की द्विमासिक बैठक भी आयोजित करने के निर्देश दिये।
- बैठक में बताया गया कि संशोधित एसएपीसीसी चरण-2 में अनुकूलन और मिटिगेशन श्रेणी के तहत 8 विभिन्न सेक्टरों को अलग-अलग कार्य समूहों में जोड़ा गया है। अनुकूलन श्रेणी के तहत इन पाँच कार्य समूहों में सतत् कृषि, जल संसाधन, वन एवं पर्यावरण सहित जैव विविधता, रणनीतिक ज्ञान और कौशल विकास तथा पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं। मिटिगेशन श्रेणी के लिये तीन कार्य समूहों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, सौर मिशन, सतत् आवास और उद्योग शामिल हैं।

हरियाणा का वाटर एटलस तैयार

चर्चा में क्यों?

11 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (HWRA) द्वारा दशकों तक काम करने के बाद अब हरियाणा का वाटर एटलस तैयार कर लिया गया है। इसे इसी महीने के अंत में लॉन्च किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- एटलस के ज़रिये अब हर साल राज्य के गिरते भू जल स्तर की जानकारी मिल सकेगी। इसके साथ ही पाँच सालों में वाटर डिमांड-सप्लाई का डाटा भी तैयार हो सकेगा। एटलस के ज़रिये होने वाले मिट्टी के कटाव और बारिश के पैटर्न को भी बताया जाएगा। एटलस के ज़रिये राज्य के किसानों को उनके क्षेत्र में जल स्तर को समझने में काफी मदद मिलेगी।
- एटलस बनाने पर काम कर रहे हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (HWRA) के अनुसार प्राधिकरण एक्विफर (जल धारण करने वाली चट्टान की भूमिगत परत) का मैप बना रहा है। इस कार्य में हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (HARSAC) भी सहयोग कर रहा है।
- राज्य के वाटर एटलस में पानी की डिमांड और सप्लाई का आने वाले 5 सालों का डाटा होगा। इसमें हर गाँव के परिवार को पानी की ज़रूरत के साथ ही गाँवों के पानी के स्रोतों को भी उल्लेख होगा। यह डाटा पानी के अंतर को मैप करने और अपशिष्ट जल का दोबारा उपयोग करने के तरीकों पर रणनीति बनाने में मदद करेगा।
- विदित है कि हरियाणा राज्य के गठन के समय से ही राज्य में भू-जल स्तर गिरता जा रहा है। हर साल भूजल में एक मीटर की गिरावट आ रही है। राज्य में औसतन भू-जल स्तर 65 मीटर है। कुरुक्षेत्र में यह 42.4 मीटर, करनाल में 22.2 मीटर, कैथल में 32.95 मीटर तक नीचे जा चुका है, जबकि महेंद्रगढ़ में भू-जल स्तर सबसे अधिक नीचे है जो 48.36 मीटर तक जा चुका है।

हरियाणा के गाँवों में अब शहरों की तर्ज पर उठेगा कूड़ा

चर्चा में क्यों?

12 दिसंबर, 2022 को हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने बताया कि नौ सूत्रीय कार्यक्रम के तहत गाँवों का शहरों की तर्ज पर विकास करते हुए अब राज्य के गाँवों में शहरों की तर्ज पर कूड़ा उठान किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- देवेंद्र सिंह बबली ने बताया कि राज्य के गाँवों में शहरों की तर्ज पर कूड़ा उठान के लिये राज्य सरकार ने NGT की गाइड लाइन लागू कर दी हैं, जिसके तहत एंड टू एंड सॉल्यूशन अनिवार्य हो गया है। इसके अलावा साफ-सफाई का जिम्मा सँभालने वाली कंपनी को गाँव की छोटी सरकार से NOC लेनी होगी, जिसके बाद ही फर्म को भुगतान किया जाएगा।

नोट :

- उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में आपसी सहमति से जन प्रतिनिधियों का चुनाव करने वाली पंचायतों को लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। सभी जन प्रतिनिधि हर सप्ताह लोगों को साथ लेकर श्रमदान करेंगे। साथ ही शहरों की तर्ज पर गाँवों में भी कलस्टर बनाकर कूड़ा प्रबंधन का कार्य किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि आने वाले 2 साल में गाँवों में बहुत बड़ा बदलाव किया जाएगा। सभी गाँवों में E-लाइब्रेरी बनाई जाएंगी जिसमें महिलाएँ व युवा बैठकर UPSC तक की तैयारियाँ कर सकेंगे। गाँवों के पुराने पंचायती भवन या समाज द्वारा बनाई गई इमारतों का सौंदर्यीकरण करके उन्हें मैरिज पैलेस की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
- गाँवों में फिरनियों को पक्का किया जाएगा तथा सोलर लाइट लगवाई जाएंगी और गाँवों के मुख्य मार्गों पर CCTV कैमरे लगाने के लिये भी ग्रामीण योजना तैयार की जाएगी। इससे गाँवों में आपराधिक गतिविधियों को रोकने में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही इन कैमरों को शहरों से कनेक्ट किया जाएगा।
- गौरतलब है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहाँ पढ़ी-लिखी और युवा पंचायतें चुनकर आई हैं। राज्य में 70 से 80 फ़ीसदी जन प्रतिनिधि 45 से 50 आयु वर्ग से नीचे की उम्र के हैं। अब विकास कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष फोकस रहेगा और सभी गाँवों में एक-एक निगरानी कमेटी बनाकर E-टेंडरिंग के माध्यम से विकास कार्य करवाए जाएंगे।

एक अप्रैल से हरियाणा में हिन्दी में भी मिलेंगे अदालतों के आदेश

चर्चा में क्यों?

13 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों व अधिकरणों में हिन्दी भाषा के उपयोग के संबंध में यह निर्णय लिया है कि अब हरियाणा में न्यायालयों के आदेश हिन्दी भाषा में भी मिलेंगे। यह आदेश एक अप्रैल 2023 से लागू होगा।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 के संशोधन करने के प्रस्ताव के संबंध में हरियाणा सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा हरियाणा राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 13) की धारा 1 की उप-धारा (2) के अधीन प्रयोजनों के उपयोग के लिये जारी अधिसूचना को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अनुमोदित कर दिया है।
- दैनिक जीवन में लोग हिन्दी भाषा का अधिकतम उपयोग करते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हिन्दी भाषा का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार आवश्यक है। इसके लिये हरियाणा मंत्रिमंडल ने जनवरी में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
- राज्य के आधिकारिक उद्देश्यों के लिये इस्तेमाल की जाने वाली भाषा हिन्दी को अपनाने के लिये हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था।
- हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 के तहत हिन्दी को हरियाणा राज्य की आधिकारिक भाषा बनाया गया। तब से हिन्दी भाषा का उपयोग ज्यादातर प्रशासन की भाषा के रूप में किया जा रहा है।
- पंजाब राजभाषा अधिनियम, 1967 में 1969 के पंजाब अधिनियम संख्या 11 के द्वारा संशोधन किया गया था, जिसमें धारा 3ए और 3बी जोड़े गए थे, कि सभी सिविल न्यायालयों और आपराधिक न्यायालयों में पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ और सभी राजस्व न्यायालय एवं अधिकरण में काम पंजाबी में किये जाएंगे।
- हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 में धारा 3ए को जोड़ा गया है, जिसके तहत पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी सिविल अदालतों और आपराधिक न्यायालयों में, सभी राजस्व अदालतें और रेंट ट्रिब्यूनलों या किसी अन्य अदालत या राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायाधिकरण, ऐसी अदालतों और न्यायाधिकरणों में कार्यवाही, कोई भी निर्णय या आदेश पारित, हिन्दी में भी होगा।

हिसार का एयरपोर्ट अभी अंतर्राष्ट्रीय नहीं

चर्चा में क्यों?

15 दिसंबर, 2022 को संसद में हिसार से भाजपा सांसद बृजेंद्र सिंह के सवाल पर केंद्रीय उड्डयन राज्यमंत्री वीके सिंह ने जवाब दिया कि हिसार से फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा अभी अंतर्राष्ट्रीय नहीं बनेगा।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय मंत्री ने बताया कि चंडीगढ़ रूट 14 जनवरी, 2021 को शुरू किया गया था। इसके बाद हिसार से देहरादून के लिये 2 फरवरी, 2021 को रूट शुरू किया गया। श्री सीटर एयरलाइन भी शुरू की गई थी।
- मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाना एयर ट्रैफिक, एयरलाइन की डिमांड, एयर स्पेशल एग्रीमेंट, ग्राउंड लैंडिंग फैसिलिटी, रनवे की लंबाई, इमीग्रेशन, हेल्थ एंड एनीमल सर्विस पर निर्भर करता है। हवाई अड्डे में फिलहाल ऐसी संभावना नहीं है।
- वहीं हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही बनेगा। इसी सोच के साथ इनका निर्माण किया जा रहा है। धीरे-धीरे उन सभी मानकों को पूरा किया जा रहा है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के लिये जरूरी होते हैं। संसद में जो जवाब दिया गया है, वह अभी के आँकड़ों के आधार पर दिया गया है।
- हिसार एयरपोर्ट के लिये 7200 एकड़ ज़मीन सिविल एविएशन को ट्रांसफर की जा चुकी है। अनुमानित खर्च बढ़कर 245.15 करोड़ रुपए हो गया है। दूसरे चरण की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 कर दी गई, पहले अक्टूबर 2022 थी। रनवे की लंबाई 10 हजार फीट करने, नाइट लैंडिंग फैसिलिटी, हैंगर बनाने, चहारदीवारी का निर्माण चल रहा है।

हरियाणा के सभी गाँवों की फिरनी पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे व लाइटें

चर्चा में क्यों?

18 दिसंबर, 2022 को हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने प्रदेश के फतेहाबाद ज़िले में जन-संवाद कार्यक्रम के तहत बताया कि प्रदेश के गाँवों की फिरनी पर लाइट व सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने बताया कि प्रदेश में गाँवों के विकास कार्यों में धनराशि की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इसके लिये प्रदेश सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत विकास कार्य ई-टेंडर के माध्यम से करवाए जाएंगे।
- उन्होंने बताया कि गाँवों में भले ही एक रुपए से लेकर 100 करोड़ रुपए तक के विकास कार्य ई-टेंडर के माध्यम से हों, लेकिन वे सभी सरपंचों की देखरेख में ही होंगे।
- उन्होंने बताया कि प्रदेश की पंचायतों में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं को दी गई है, जो कि महिला सशक्तीकरण का एक उदाहरण है। सरकार की दूरगामी सोच के तहत ही प्रदेश में पढ़ी-लिखी पंचायतें बनी हैं, जिसमें युवाओं की खासी भागीदारी सामने आई है।
- उन्होंने बताया कि सभी गाँवों की फिरनी पर लाइट व सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। प्रदेश भर की तीन लाख किलोमीटर फिरनी में से पहले चरण में एक लाख किलोमीटर फिरनी पर कार्य किया जाएगा।
- इसी प्रकार से प्रदेश सरकार ने गाँवों में जलभराव की समस्या से निपटान के लिये ग्रे वाटर मैनेजमेंट के तहत कार्य शुरू किया है, जिसमें जलभराव वाले चिह्नित किये गए 3500 गाँवों में से 1000 गाँवों में कार्य शुरू हो चुका है। जलभराव की समस्या से निजात पर सरकार द्वारा 18 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे।
- उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से यह भी आह्वान किया कि वे गांव के सामुदायिक केंद्र व स्कूल आदि सार्वजनिक संपत्तियों के रख-रखाव पर पूरा ध्यान दें। प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी ईमारतों व भवनों का जीर्णोद्धार तथा नव-निर्माण किया जा रहा है। गाँवों में डिजिटल लाइब्रेरी खोली जा रही है, जहाँ पर गाँव के युवा यूपीएससी आदि प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे।

नोट :

हरियाणा ने जीता स्कॉच गोल्ड अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

19 दिसंबर, 2022 को नई दिल्ली स्थित इंडिया हेबिटेट सेंटर में आयोजित समारोह में हरियाणा के कृषि व बागवानी विभाग को मृदा स्वास्थ्य कार्ड और फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम में अपनी-अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिये स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला।

प्रमुख बिंदु

- यह अवार्ड हरियाणा की ओर से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा एवं बागवानी विभाग के महानिदेशक अर्जुन सैनी ने प्राप्त किया।
- राष्ट्रीय पूल में खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाले हरियाणा प्रदेश ने बागवानी की दिशा में विविधीकरण और कृषि-व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिये कई नीतिगत पहल की हैं। राज्य ने लगभग 400 बागवानी फसल समूहों की मैपिंग की है और 700 किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया है।
- क्लस्टर में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को मजबूत करने के लिये राज्य ने एफपीओ के माध्यम से ऑन-फार्म इंटीग्रेटेड पैक-हाउस की स्थापना के लिये 510.35 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक महत्त्वाकांक्षी योजना 'फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीसीडीपी)' शुरू की है। प्रदेश में अब तक 33 एकीकृत पैक-हाउस स्थापित किये जा चुके हैं और 35 प्रगति पर हैं। चालू वित्त वर्ष के अंत तक ऐसे कुल 100 एकीकृत पैक हाउस स्थापित करने का लक्ष्य है।
- इसके अलावा, किसानों और कृषि उपज के लिये अंतिम मूल्य श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिये कृषि क्षेत्र की 37 कंपनियों ने कृषि-व्यवसाय गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये बाय-बैक तंत्र के साथ एफपीओ के उत्पादन के व्यापार और विपणन के लिये 34 एफपीओ के साथ 54 समझौता ज्ञापन निष्पादित किये हैं।
- गौरतलब है कि सीसीडीपी को उपज के एकत्रीकरण सहित कई मुद्दों को हल करने के लिये लॉन्च किया गया था, जैसे - क्लस्टर गठन, किसान समूह और पैक-हाउस, संग्रह केंद्र, ग्रेडिंग-पैकिंग और मानक जैसे बाजार लिंकेज आदि।
- इसके अलावा, इसका उद्देश्य कीटनाशकों के अवशेषों, और कीटों, बीमारियों, एफ्लाटॉक्सिन और भारी धातुओं सहित सूक्ष्म जीवविज्ञानी संदूषण सहित स्वच्छता और फाइटोसैनेटिक उपायों को हल करना भी है।
- राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि 'हर खेत-स्वस्थ खेत' अभियान के तहत 3-4 वर्षों में लगभग 75 लाख मिट्टी के नमूने एकत्र कर उनका परीक्षण किया जाएगा और प्रत्येक एकड़ के लिये मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) किसानों को वितरित किये जाएंगे।
- मृदा परीक्षण के बारे में लोगों की भागीदारी और जागरूकता बढ़ाने के लिये मिट्टी के नमूने एकत्र करने और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण का कार्य किसान सहायकों, (स्थानीय ग्रामीणों) और 'अर्न व्हाइल यू लर्न'कार्यक्रम के तहत सरकारी कॉलेजों, सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के विज्ञान छात्रों के माध्यम से किया जा रहा है।
- किसान सहायकों और विज्ञान के छात्रों को प्रति मिट्टी का नमूना के लिये 40 रुपए का प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है। मिट्टी के नमूने लेने के लिये उन्हें विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। इसी रणनीति से राज्य ने वर्ष 2022-23 में 30 लाख मिट्टी के नमूने एकत्र किये हैं, जो पिछले वर्षों (2015-2020) की तुलना में आठ गुना ज्यादा है।
- प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा राज्य में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का एक विस्तृत नेटवर्क है जहाँ किसानों की मिट्टी परीक्षण के लिये आसान पहुँच है। 20-25 किलोमीटर की परिधि में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की उपलब्धता है।
- वर्ष 2020-21 से पहले विभाग 35 स्थैतिक मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ, जो सालाना 7.4 लाख मिट्टी के नमूनों का परीक्षण कर सकती थीं। वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान विभाग ने 60 नए एसटीएल (13 स्थिर+47 मिनी) बनाए हैं।
- वर्तमान में विभाग के पास कुल 95 (48 स्थिर+47 मिनी) मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं जो सालाना 30 लाख मिट्टी के नमूनों का परीक्षण कर सकती हैं।

नोट :

सॉफ्टवेयर से तैयार होगी प्रदेश में ज़मीन की फर्द

चर्चा में क्यों?

20 दिसंबर, 2022 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य के सिरसा ज़िले के गाँव मिठी सुरेरां में आयोजित कार्यक्रम में बताया कि प्रदेश में ज़मीन की फर्द तैयार करने के लिये नया सॉफ्टवेयर लिया गया है। इससे अब किसानों को अपनी ज़मीन की फर्द लेने के लिये पटवारखानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

प्रमुख बिंदु

- दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो फर्द, यानी जमाबंदी निकाली जाएगी, उस पर क्यूआर कोड अंकित होगा। क्यूआर कोड अंकित होने के कारण ही इस फर्द को वेरीफाइड डॉक्यूमेंट माना जाएगा।
- उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने यह सॉफ्टवेयर केंद्र सरकार से खरीदा है और इस सॉफ्टवेयर से जो जमाबंदी निकाली जाएगी, उससे किसान ऋण भी ले सकेंगे और पटवारी से हस्ताक्षर करवाने की भी ज़रूरत नहीं होगी।
- इसके अलावा उपमुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अब बीपीएल कार्ड बनवाने के लिये लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि आगामी एक जनवरी से एक लाख 80 हज़ार रुपए सालाना से कम आय वाले परिवारों की वेरीफाई आय के आधार पर बीपीएल कार्ड अपने आप ही बन जाएंगे।
- उन्होंने बताया कि सरकार ने टेक्नोलॉजी की मदद से न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार की है कि अब लोगों को घर-बैठे ही सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और अब लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।

हैफेड रेवाड़ी में स्थापित करेगा ऑयल-मिल

चर्चा में क्यों?

20 दिसंबर, 2022 को हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने चंडीगढ़ में सहकारिता विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद बताया कि हैफेड द्वारा रेवाड़ी ज़िला के रामपुरा में नई ऑयल-मिल स्थापित की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- इस मिल के स्थापित होने से जहाँ मार्केट में बढ़ रही सरसों के तेल की डिमांड को पूरा करने में लाभ होगा, वहीं प्रदेश के किसानों द्वारा पैदा की जा रही सरसों की खपत भी सही हो सकेगी। इस मिल की पिराई क्षमता आरंभ में 150 टीपीडी होगी, परंतु इसको बाद में 300 टीपीडी तक बढ़ाया जा सकता है।
- इस मिल की स्थापना होने से जहाँ करीब 500 लोगों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे, वहीं इससे दक्षिण हरियाणा के लगभग 50 हज़ार किसानों को फायदा होगा।
- डॉ. बनवारी लाल ने राज्य में हल्दी-प्लांट व इसमें ऑयल ,पाउडर तथा अन्य मसालों व कोल्ड स्टोर बनाने के कार्य के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हुए कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने के निर्देश दिये।
- इसके अलावा उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में वीटा-कैफे खोले जाएंगे, ताकि लोगों को वीटा दूध एवं दूध से बने गुणवत्तापरक उत्पाद मिल सकें। गुरुग्राम में वर्तमान में करीब एक दर्जन हैफेड के सेल्स आऊटलेट्स हैं, अब वहाँ पर डेयरी विकास प्रसंघ एवं हैफेड बूथ अथवा शोरूम खोले जाएंगे।
- गौरतलब है कि हैफेड हरियाणा की सबसे बड़ी एवं शीर्ष सहकारी संघ है। यह 1 नवंबर, 1966 को एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा के गठन के साथ ही अस्तित्व में आया।

नोट :

महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर हरियाणा व केंद्र सरकार में समझौता

चर्चा में क्यों?

21 दिसंबर, 2022 को हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हिसार में बनने वाले महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर हरियाणा व केंद्र सरकार में समझौता हो चुका है तथा इस मेगा प्रोजेक्ट के लिये राज्य सरकार ने 945 करोड़ रुपए का बजट रखा हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिसार एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है। यह 7200 एकड़ में विस्तृत हरियाणा का पहला बड़ा एयरपोर्ट होगा है।
- हिसार एयरपोर्ट का निर्माणाधीन रनवे 10 हज़ार फुट का है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अनुरूप है। पिछले डेढ़ वर्ष में रनवे का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया तथा मार्च 2023 में यह रनवे तैयार हो जाएगा।
- इस रनवे के साथ-साथ टैक्सी स्टैंड और 23 मीटर चौड़ा टैक्सी-वे, पार्किंग स्टैंड, फायर स्टेशन का निर्माण भी इंटरनेशनल मानकों के हिसाब से किया जा रहा है। अत्याधुनिक तकनीक वाली लाइट जिससे रात में भी हवाई जहाज लैंड कर सकते हैं तथा लेटेस्ट टेक्निक वाला एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि दुनिया भर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवाई पट्टियों की लंबाई 9 हज़ार से लेकर 12 हज़ार फीट तक है, जबकि हिसार के हवाई पट्टी की लंबाई 10 हज़ार फीट है।
- उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि द्वितीय चरण का निर्माण होने के बाद एयरपोर्ट के टर्मिनल और एप्रन का निर्माण भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टैंडर्ड के तहत किया जाना है।
- उन्होंने बताया कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही नहीं, बल्कि इसे एविएशन हब बनाया जाएगा। लगभग 7200 एकड़ भूमि में एयरपोर्ट विकसित होने के अलावा 3000 एकड़ में मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित करने के लिये जल्द कार्य शुरू किया जाएगा।
- इस एयरपोर्ट के बनने से अमृतसर से लेकर जयपुर तक के यात्रियों को सुविधा प्राप्त होगी।

हरियाणा में रेल अवसंरचना परियोजनाओं के लिये 128 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण स्वीकृत

चर्चा में क्यों?

22 दिसंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एचआरआईडीसी) की बैठक में रेल अवसंरचना परियोजनाओं के लिये एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) से 128 मिलियन अमरीकी डॉलर (1040 करोड़ रुपए) का ऋण स्वीकृत किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में मुख्य सचिव ने बताया कि आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली और महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, हिसार वाया बिजवासन-गुरुग्राम, बसई-धनकोट, सुल्तानपुर-फरुखनगर, झज्जर, अस्थल बोहर-रोहतक, डोभ-भाली, हांसी-हिसार एयरपोर्ट के बीच रेलवे कनेक्टिविटी के लिये एचआरआईडीसी एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है।
- उन्होंने बताया कि दूसरे 'अर्बन इंफ्रा बिजनेस सबमिट एंड अवाड्र्स, 2022' के अवसर पर 'न्यू रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट' में उत्कृष्टता के लिये 'अर्बन इंफ्रा ग्रुप' द्वारा रेल क्षेत्र में अच्छी तरह से स्थापित कंपनियों के साथ एचआरआईडीसी को सम्मानित किया गया है।
- एचआरआईडीसी का गुरुग्राम में स्थायी प्रधान कार्यालय होगा जिसके लिये राज्य सरकार ने सेक्टर 32 में एक भूखंड आवंटित कर दिया है।
- मुख्य सचिव ने बैठक में अधिकारियों को राज्य में रेल संपर्क विस्तार के लिये हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के लिये भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये। इसके तहत 130 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में सोहना से पलवल तक 17 स्टेशनों वाली एक नई दोहरी रेल लाइन बादली, मानेसर और सोहना से होकर कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे के साथ-साथ चलेगी।

'मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना' का विस्तार

चर्चा में क्यों ?

22 दिसंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में बताया कि राज्य में 20 साल से अधिक समय से किराये या लीज पर चल रही पालिकाओं की व्यावसायिक भूमि की मलकियत उन पर काबिज व्यक्तियों को देने के लिये बनाई गई 'मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना' को अन्य विभागों द्वारा भी अपनाया जाएगा। इसके लिये नए सिरे से योजना का खाका तैयार किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना का प्रारूप 15 दिनों में तैयार करें। तत्पश्चात् प्रारूप को मुख्यमंत्री तथा वित्त विभाग की मंज़ूरी के लिये भेजा जाएगा और अंतिम मंज़ूरी हेतु मंत्रिपरिषद की बैठक में लाया जाएगा।
- मुख्य सचिव ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना जून 2021 में बनाई गई थी। इसके तहत शहरी निकायों के उन सभी नागरिकों को मालिकाना हक प्रदान किया गया, जिनके पास व्यावसायिक भूमि का 20 साल या 20 साल से अधिक कब्ज़ा है।
- इस योजना के तहत जो व्यक्ति किराये या लीज के माध्यम से भूमि पर 20 साल से काबिज हैं, उन्हें कलेक्टर रेट का 80 प्रतिशत तक भुगतान करने पर मालिकाना हक दिया जा रहा है।
- इसी प्रकार, भूमि पर काबिज वर्षों की सीमा के अनुसार क्लेक्टर रेट का अलग-अलग दर पर भुगतान करना होगा, जैसे- 25 साल तक काबिज व्यक्ति को कलेक्टर रेट का 75 प्रतिशत, 30 साल तक 70 प्रतिशत, 35 साल तक 65 प्रतिशत, 40 साल तक 60 प्रतिशत, 45 साल तक 55 प्रतिशत और 50 साल तक 50 प्रतिशत का भुगतान करने पर मालिकाना हक दिये जाने का प्रावधान है।
- उन्होंने बताया कि अब राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि निकायों के अलावा अन्य विभागों की ज़मीनों पर भी इसी प्रकार से नागरिकों को मालिकाना हक देने के लिये प्रदेशभर में एकरूपता लाते हुए नए सिरे से योजना बनाई जाएगी।
- उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि अन्य विभागों के लिये इस योजना का प्रारूप शहरी स्थानीय निकाय विभाग ही तैयार करे और इस प्रारूप को संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ साझा किया जाएगा और उनसे टिप्पणियां माँगी जाएंगी।
- बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के पहले चरण के दौरान लगभग 7 हज़ार आवेदन आए थे। 1730 आवेदकों को लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) जारी हो चुके हैं।

राज्य में अब स्टेज- 3 व 4 के कैंसर पीड़ितों को मिलेगी 2500 रुपए मासिक पेंशन

चर्चा में क्यों ?

23 दिसंबर, 2022 को हरियाणा सरकार ने प्रदेश के स्टेज- 3 व 4 के कैंसर पीड़ितों के लिये 2500 रुपए मासिक पेंशन आरंभ करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकार के खजाने पर 68 करोड़ 42 लाख रुपए से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मई, 2022 में कैंसर पीड़ितों के परिवार से मिलने के बाद आश्वासन दिया था कि कैंसर पीड़ितों की हरसंभव मदद की जाएगी तथा जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है, यह सहायता उन मरीज़ों को दी जाएगी।
- राज्य के सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग ने बताया कि इस योजना के लाभ के लिये परिवार पहचान-पत्र में दर्शाई गई वार्षिक आय के तथ्यों से मिलान किया जाएगा। यह पेंशन मरीज़ के जीवित रहने तक जारी रहेगी।
- इस योजना का लाभ लेने के लिये मरीज़ को सिविल सर्जन कार्यालय की कमेटी द्वारा सत्यापित दस्तावेज़ों को सरल केंद्र के माध्यम से अपलोड कराना होगा। आवेदक को राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, टेलीफोन, पानी, बिजली या अन्य उपयोगिता वाले बिल, जिसमें घर का पता अंकित हो या भू-रिकॉर्ड के दस्तावेज/परिवार पहचान-पत्र को सरल केंद्र में साथ लाना होगा।

नोट :

- आशा वर्कर/ एएनएम मरीज़ के जीवित होने के प्रमाण-पत्र को सत्यापित करेगी, जिसे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाएगा।
- नागरिक संसाधन सूचना विभाग के अनुसार हरियाणा में 57 लाख परिवार हैं, जिनकी जनसंख्या 2 करोड़ 85 लाख है। इनमें से 45 लाख से अधिक परिवार ऐसे हैं, जिनकी सालाना आय परिवार पहचान-पत्र में 3 लाख रुपए से कम है।
- उल्लेखनीय है कि राज्य में राहत कोष से कैंसर पीड़ितों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पूर्व में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा स्वीकृत की जाती थी। संबंधित ज़िला उपायुक्त द्वारा मामला मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा जाता था और यह एक लंबी प्रक्रिया थी। मुख्यमंत्री के संज्ञान में जैसे ही यह मामला आया तो उन्होंने ज़िला उपायुक्त को ही अपने स्तर पर यह वित्तीय सहायता राशि जारी करने को कहा। 1 लाख रुपए तक की यह राशि मरीज़ को आर्थिक मदद के तौर पर ज़िला स्तर पर दी जाती है।
- राज्य सरकार ने कैंसर मरीज़ों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए यह निर्णय लिया है कि अगर मरीज़ किसी अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन या वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ ले रहा है तो उसे भी 2500 रुपए की मासिक पेंशन अतिरिक्त रूप से मिलती रहेगी।
- गौरतलब है कि हरियाणा से पहले देश में केवल त्रिपुरा ही एक ऐसा राज्य है, जो स्टेज-3 के कैंसर पीड़ितों को 1000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता दे रहा है।

हरियाणा अनुसूचित जाति (एससी) आयोग का गठन

चर्चा में क्यों?

26 दिसंबर, 2022 को हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनुसूचित जाति (एससी) आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन फतेहाबाद ज़िले के रतिया के पूर्व विधायक प्रो. रविंद्र बलियाला को नियुक्त किया गया है।
- आयोग के वाइस चेयरमैन भिवानी के विजय बदबुजार को बनाया गया है तथा कैथल के रावी तारांवाली, सोनीपत की मीना नरवाल और सिरसा के रतन लाल को सदस्य नियुक्त किया गया है।

सूर्य नमस्कार अभियान

चर्चा में क्यों?

26 दिसंबर, 2022 को हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉ. जयदीप आर्य की अध्यक्षता में प्रदेश के मुरथल में ज़िला आयुष विभाग एवं हरियाणा योग आयोग के संयुक्त तत्त्वावधान में हुई बैठक में बताया कि आज़ादी की 75वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में 11 जनवरी से 12 फरवरी तक सूर्य नमस्कार अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिये 75 लाख सूर्य नमस्कार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. जयदीप आर्य ने बताया कि सूर्य नमस्कार अभियान का शुभारंभ अंबाला में प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज करेंगे, जबकि समापन सोनीपत के खानपुर कलां के भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में राज्यस्तरीय कार्यक्रम के आयोजन के साथ किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल होंगे।
- उन्होंने बताया कि सूर्य नमस्कार की शुरुआत स्वामी विवेकानंद की जयंती (12 जनवरी) के पूर्व दिवस पर की जाएगी और समापन स्वामी दयानंद जयंती (12 फरवरी) पर किया जाएगा। हर व्यायामशाला व हर गाँव में सूर्य नमस्कार का आयोजन करवाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिये योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संवर्द्धन समिति का गठन किया जाएगा।
- डॉ. जयदीप आर्य ने बताया कि हरियाणा देश का पहला एकमात्र राज्य है, जहाँ योग को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। पाठ्यक्रम में केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, प्रायोगिक रूप को भी महत्त्व दिया गया है।
- उन्होंने योगाचार्यों व योग प्रेमियों का आह्वान किया कि वह योग पर पुस्तकों की रचना कर सकते हैं, जिन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। चयनित पुस्तक पर रचनाकार को 50 हज़ार रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, शोधकार्य करने वालों को भी 50 हज़ार रुपए का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा।

नोट :

- उन्होंने बताया कि योग हेतु कुरुक्षेत्र में 20 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें एक साथ 2000 व्यक्तियों के लिये योग साधना करने की व्यवस्था रहेगी। साथ ही 200 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना भी की जाएगी।
- हरियाणा योग आयोग की तरफ से विदेशी भाषा केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, जिसमें योग सहायकों को विदेशी भाषा का प्रशिक्षण देकर उन्हें संस्कृति राजदूत बनाकर विदेशों में भेजा जाएगा।

ड्यूकेन मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी के मरीज़ों को मिलेगी 2500 रुपए पेंशन

चर्चा में क्यों?

27 दिसंबर, 2022 को हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में ड्यूकेन मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी सहित दुर्लभ रोगों से पीड़ित रोगियों को 2500 रुपए प्रति माह पेंशन दिये जाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने बताया कि प्रदेश में इस बीमारी के मरीज़ों की संख्या 400 से 500 है।
- उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश सहित कुछ राज्य डयूकेन मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी पीड़ितों को मासिक पेंशन दे रहे हैं।
- उन्होंने बताया कि दुर्लभ रोगों की राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत डयूकेन डस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी सहित दुर्लभ रोगों से पीड़ित रोगियों को उत्कृष्ट केंद्रों में उपचार के लिये 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- केंद्र सरकार ने इसके लिये 10 एक्सीलेंस सेंटर बनाए हैं। पीजीआई चंडीगढ़ भी उनमें शामिल है।

सोनीपत में बनेगा प्रदेश का पहला खेलकूद विश्वविद्यालय

चर्चा में क्यों?

27 दिसंबर, 2022 को हरियाणा के खेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महाबीर सिंह ने बताया कि राज्य के सोनीपत ज़िले में स्थित मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल में प्रदेश का पहला खेलकूद विश्वविद्यालय बनेगा।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार राज्यपाल बंडारु दत्तात्रेय ने पानीपत के गाँव अटावला निवासी सेवानिवृत्त आईपीएस एस.एस देशवाल को नए खेल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है।
- खेलकूद स्कूल को खेलकूद विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड नहीं किया जाएगा। बल्कि खेलकूद स्कूल परिसर में अलग से विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।
- गौरतलब है कि विगत दिनों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत के राई स्थित मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल में प्रदेश का पहला खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की थी।
- खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये कागजी कार्रवाई समेत अन्य प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब खेलकूद स्कूल परिसर में विश्वविद्यालय के लिये आधारभूत संरचना को तैयार करना है। इससे पूर्व खेलकूद विश्वविद्यालय की विधिवत रूप से शुरुआत कर दी गई है। सरकार ने खेलकूद स्कूल को इससे संबंधित पत्र भी भेजा है।
- विदित है कि वर्ष 1973 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल ने राई में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल की शुरुआत की थी। स्कूल के खिलाड़ी अब तक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपने प्रदर्शन से अनेक पदक जीत चुके हैं। यही नहीं अनेक प्रशासनिक सेवा व सेना में बड़े पदों पर काम कर रहे हैं।
- राज्य सरकार की योजना के अनुसार यहाँ हर खेल के लिये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक व खिलाड़ी तैयार हो सके।
- हरियाणा एक खेल प्रदेश है, जहाँ एक भी खेल विश्वविद्यालय नहीं था। खिलाड़ियों को एनआईएस प्रमाणपत्र या पाठ्यक्रम के लिये दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता था। इसे देखते हुए यहाँ खेलकूद विश्वविद्यालय शुरू किया गया है। यहाँ खेल से संबंधित सभी पाठ्यक्रम कराए जाएंगे।
- मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल में हॉकी, फुटबॉल, घुड़सवारी, तैराकी, जिमनास्ट, बास्केटबॉल के अलावा 12 खेलों के मैदान हैं। घुड़सवारी व तैराकी में राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल का लंबे समय से दबदबा रहा है। स्कूल में खेलों को बढ़ावा देने के लिये बहुउद्देशीय हॉल व हॉकी का एस्टोटर्फ मैदान हैं। यहाँ 50 मीटर शूटिंग रेंज बनाई जा रही है। पहले से बने तरणताल व अन्य खेल मैदान राष्ट्रीय स्तर के हैं।

नोट :

पंचायतों और नगर पालिकाओं को और अधिक स्वायत्तता देगी हरियाणा सरकार

चर्चा में क्यों ?

28 दिसंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रदेश में पंचायतों, ब्लॉक समिति, ज़िला परिषद, नगर पालिकाओं, नगर परिषद और नगर निगमों को और अधिक स्वायत्तता देने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि ग्राम पंचायतों के अंतर्गत सरपंच 2 लाख रुपए तक के कार्य कोटेशन आधार पर अपने स्तर पर करवा सकेंगे तथा 2 लाख रुपए से अधिक के कार्य हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर टेंडर के माध्यम से होंगे।
- नई व्यवस्था के तहत उपमंडल स्तर पर 2 लाख से 25 लाख रुपए तक के कार्य एसडीओ ही अप्रूव करेगा। सरपंच, ब्लॉक समिति व ज़िला परिषद के चेयरमैन इसके लिये प्रशासनिक स्वीकृति देंगे। पहले कार्यों की अप्रूवल की फाइलें निदेशक तक आती थीं, अब स्थानीय स्तर पर ही सभी मंज़ूरी मिलेंगी।
- उन्होंने बताया कि 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के कार्यों की तकनीकी मंज़ूरी अधिशाषी अभियंता देगा और अनुमोदन सीईओ, ज़िला परिषद करेंगे तथा 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक के कार्यों की तकनीकी मंज़ूरी अभियंता अधीक्षक देंगे और अप्रूवल पंचायत निदेशक की ओर से दी जाएगी। 2.5 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य की तकनीकी मंज़ूरी चीफ इंजीनियर या इंजीनियर इन चीफ की ओर से दी जाएगी। इसका अनुमोदन प्रशासनिक सचिव करेंगे।
- पंचायती राज संस्थानों को राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त बजट कम पड़ता है तो ग्रामीण विकास विभाग, एचआरडीएफ या राज्य सरकार के अन्य रिज़र्व फंड से मांग आधारित बजट उपलब्ध करवाएगा।
- इन निधि से जो कार्य किये जाएंगे, उनमें 25 लाख रुपए तक के कार्य की स्वीकृति पंचायत निदेशक देंगे। 25 लाख रुपए से अधिक के कार्य ग्रामीण विकास विभाग करवाएगा और मंज़ूरी सरकार देगी। 5 से 10 करोड़ रुपए तक के कार्य संबंधित मंत्री और 10 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य मुख्यमंत्री के पास आएंगे।

डिजिटल मीडिया सेक्शन को मिला राज्य स्तरीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस के अवसर पर पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सूचना, जन संपर्क और भाषा विभाग (डीआईपीआरएल) के डिजिटल मीडिया सेक्शन को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- यह पुरस्कार सरकारी योजनाओं के प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका निभाने और फैक्ट चेक अकाउंट्स के ज़रिये फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिये प्रदान किया गया। इस अवसर पर डिजिटल मीडिया सेक्शन के इंचार्ज (सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी) आदित्य चौधरी और सहायक प्रबंधक अरविंद कुमार ने मुख्यमंत्री से पुरस्कार प्राप्त किया।
- गौरतलब है कि सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा डिजिटल मीडिया सेक्शन बनाया गया है ताकि सरकार से संबंधित आवश्यक सूचना, नवीनतम योजनाओं की जानकारी और अधिसूचनाओं की जानकारी प्रभावी और प्रामाणिक माध्यम से लोगों तक समय पर पहुँचे।
- विदित है कि डिजिटल मीडिया सेक्शन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रेरक नेतृत्व में तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के प्रधान सचिव अनुराग अग्रवाल और सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित कुमार अग्रवाल के सक्षम और निरंतर मार्गदर्शन में काम कर रहा है।
- डिजिटल मीडिया सेक्शन की ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित 11 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली उपस्थिति है। यह सेक्शन फर्जी समाचारों एवं सूचनाओं की जाँच करके अपने फैक्ट चेक अकाउंट के माध्यम से तुरंत प्रतिक्रिया देता है और सरकारी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का प्रसार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

नोट :